TURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) A statement indicating the State-wise damages due to floods and heavy rains during current monsoon period as reported by the affected States, is given enclosed . [*See* Appendix CXLVII, Annexure No. 99].

(b) Rs. 362.50 lakh to Assam and Rs. 37.50 lakhs to Tripura has been released as Central Share of Margin Money.

(c) No, Sir.

सुपर बाजार के माध्यम से बिक्री

2298. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के दृष्टिकोण से सुपर बाजार के माध्यम से वस्तुएं बेचने की व्यवस्था की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जुलाई माह के दौरान जब खुले बाजार में चीनी का मूल्य बढ़ गया था, तब चीनी के भंडार की कमी के करण सुपर बाजार भी चीनी की बिक्री नहीं कर सका ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस प्रकार की कुव्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । सुपर बाजार द्वारा जुलाई, 1988 में लगभग 903 मी० टन चीनी बेची गयी थी, जबकि जून, 1988 में 648 मी० टन, मई में 66 मी० टन तथा अप्रैल, 1988 में 497 मी० टन चीनी बेची गई थी ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Arrears of Employees Provident Fund

2299. SHRI ASHIS SEN:

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Employees Provident Fund Organisation functioning for the welfare of the employers has detected mounting arrears from both unexempted and exempted establishments; and

(b) if so, what was the quantum of arrears during 1986-87 and 1987-88, in both the cases?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) Yes Sir.

(b) The arrears of Provident Fund Contribution at the end of 1986-87 (31-3-87) and 31-12.87 was as given below:—

	31-3-1987	31-12-1987
	(Rupees in crores)	
Unexempted Establishments	71-97	74-34
Exempted Establishments	98-51	104-13

Subscription to EPF

2300. SHRI MOHAMMED AMIN Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the steps taken to nab errant employers, both of unexempted and exempted establishments, who d

not subscribe to E.P.F. in provident fund securities; and

(b) the amount involved in such cases?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) The E.P.F. authorities are generally taking the following action for realisation of the outstanding dues:—

(i) Issuing of Recovery Certificates under Section 8 of the EPF Act for recovery of dues in respect of unexepmted establishments;

(ii) Filling of prosecution cases under section 14 of the EPF Act in resepect of unexempted establishments;

(iii) Filing of prosecution cases under section 14(2A) of the EPF Act in cases of default on the part of exempted establishments.

(iv) Filing of complaints under section 406/409 IPC in cases of nonpayment of ocntribution deducted from the wages of the employees;

(v) Levying of damages under section 14 B of the E.P.F. Act.

(b) The amount of E.P.F. Contribution in arrears as on 31-2-1987 was as given below:—

Rupees in crores

(i) Unexempted establishments . . .	74.34
(ii) Exempted establishments . . .	104.13

Review of working of Employees' Provident Fund Organisation

2301. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether any review is being conducted on the working of the Employees' Provident Fund Organisation; and

(b) if so, by when the review is likely to be completed and the outcome would be made public?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARY DUBEY): (a) and (b) Reveiw of the working of the E.P.F. Organisation is a continuing feature. This is done both by the Central Board of Trustees of the Organisation, as also by the Ministry.

These reviews are in the nature of administrative reviews and not external to the Organisation, and therefore, the question of making such reivews public does not arise. In any case the Annual Report of the E.P.F' Organisation is placed on the Table of the House every year.

खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार

2302. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1988 के महीने के दौरान देश में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार लगभग 150 लाख टन था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने के लिये प्रति माह कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये देश में खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिये अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये गये है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) सरकारी एजेंसियों के पास पहली जून, 1988 की स्थिति के अनुसार 133.8 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक होने का अनुमान था ।